शहरी विकास, भू प्रशासन, बैंकिंग, आपदा प्रबंधन व आपूर्ति सेवाओं में होगी आसानी

783 निकायों के मानचित्र और 14455 वार्डों का जियो-स्पेशियल डाटाबेस तैयार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। जनगणना कार्य निदेशालय उप्र और स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी 75 जिलों के 783 नगर निकायों के मानचित्र और उनके 14,455 वार्डों के जियो-स्पेशियल डाटाबेस संयुक्त रूप से तैयार किए हैं। बृहस्पतिवार को जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक नितिन बंसल को यह डाटाबेस सौंपा।

जियो-स्पेशियल डाटाबेस राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि और विकसित हो रही डिजिटल व सूचना आधारित अर्थव्यवस्था के अध्ययन और क्षेत्रवार विशेषताओं के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह शहरी विकास, भू प्रशासन, बैंकिंग व वित्तीय आर्थिक गतिविधियों, जल, आपदा प्रबंधन और आपूर्ति सेवा में उपयोगी है। इसे राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति-2022 के लिए भी तैयार किया गया है। भू-स्थानिक आंकड़ों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे व सूचना स्रोत में किया जाता है।

इसी के तहत जनगणना कार्य निदेशालय, उप्र ने भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय नई दिल्ली के निर्देशों के अंतर्गत शहरी ढांचे के राष्ट्रीय भू-स्थानिक डाटाबेस के लिए राज्य के सभी 783 नगर निकायों के 14,455 वार्ड

जनगणना निदेशक ने स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक को सौंपा डाटाबेस

जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक नितिन बंसल को जियो-स्पेशियल डाटाबेस सौंपा। -विभाग

सीमाओं के जियो-स्पेशियल वार्ड मानचित्र बनवाने का निर्णय लिया। जियो-स्पेशियल डाटाबेस तैयार करने के लिए नगर निकायों के अधिशाषी अधिकारियों को पिछले साल को प्रशिक्षण दिया गया था। नगर निकायों कार्यालय के कम से कम दो ऐसे अधिकारी जो अपने नगर की वार्ड सीमाओं के सड़कों, गलियों, लैंडमार्क व भवनों के जानकार थे और गूगल मैप में वार्ड की सीमाओं को पहचानने में सक्षम थे, उनकी भी मदद ली गई।

नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण में जियो-स्पेशियल मैपिंग की वृहद उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्रमशः सभी 168 सेक्टरों, 110 सेक्टरों व 33 सेक्टरों की अलग-अलग जियो-स्पेशियल मैपिंग के लिए विशेष नीति अपनाई गई। यह काम तय समयसीमा से दो महीने पहले 4 नवंबर 2023 को पूरा कर लिया गया। वहीं, तैयार जियो-स्पेशियल डाटाबेस भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय से जांच के बाद आठ अप्रैल को जनगणना कार्य निदेशालय, उप्र को मिल गया। अब शासन द्वारा इन मानचित्रों को तकनीकी रूप से मूल्यांकन और संबंधित नगर निकाय से सीमाओं की पुष्टि के बाद अंतिम रूप देते हुए विभिन्न स्टेकहोल्डर को दिया जाएगा।

शीतल वर्मा ने बताया कि विकास के लिए प्रशासनिक स्तर की सबसे छोटी इकाई तक जियो-स्पेशियल मानचित्र के रूप में डिजिटाइज करना आवश्यक है। जियो-स्पेशियल वार्ड सीमा, नगरीय क्षेत्रों में जनगणना के सर्वे कार्य में दोहराव आदि की समस्या को खत्म करने में अहम होगा। वहीं, नितिन बंसल ने कहा कि नगर निकायों में इसका उपयोग कर नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता के डिजिटल ओपन सोर्स को विकसित करने, नागरिक सुविधाओं के विकास में व्यय होने वाले जन धन का विवरण देने जैसे कई काम आसान होंगे।